tara chand
logistic solutions ltd
Think New. Act Now

Pan No. AAECT1408Q
TAN No.PTLT12766F
GSTIN. 04AAECT1408Q1Z8
CIN No. L63090CH2012PLC033556

Registered Office : 342, Industrial Area, Phase-1, Chandigarh -160 002
Ph. : 0172- 2650380, 2654928 | E : info.chd@tarachandindia.in | www.tarachandindia.in

Date: 03/08/2019

To,
The Secretary,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor Plot No - 'C' Block,
G Block Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051

Dear Sir/Madam,

Please refer to our intimation dated August 02, 2019 whereby the Company had made submission under Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (LODR) regarding newspaper intimation of notice of the 7thAnnual General Meeting ('AGM') of the Company to be held on Friday, 23rdAugust, 2019 at 10:30 A.M.at the Fern Residency, 28/8, Phase II, Industrial & Business Park, Chandigarh – 160002, which was published on 2nd August, 2019, in one English newspaper having nationwide circulation i.e. (Business Standard in English Language)and one in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district in which the registered office of the company is situated i.e. (Business standard in regional language).

Kindly note that the date till which the Register of Members and Share Transfer Books of the Company remained closed has been inadvertently mentioned as September 23, 2019 in the aforementioned submission in the vernacular language Newspaper i.e. Business Standard in Hindi language in place of August 23, 2019, being a typographical error.

Kindly note the correct date till which the Share Transfer Books of the Company will remain closed is August 23,2019.

For and on behalf of Board of Directors of
Tara Chand Logistic Solutions Limited

TARA CHAND LOGISTIC SOLUTIONS LTD.

Nishu Kansal
Company Secretary & Compliance Officer

अमेरिका, चीन के बीच तनाव से दो प्रतिस्पर्धी गुटों के उदय की संभावना

अमेरिका–चीन में बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा कि वह आने वाले समय में दो प्रतिस्पर्धी गुटों के उभार की संभावनाएं देख रहे हैं, जिनका अपने अपने मुद्रा, व्यापार और सैन्य मोर्चे पर वर्चस्व होगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन पिछले एक साल से व्यापार युद्ध में उलझे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप चीन से भारी व्यापार घाटा कम करने की मांग कर रहे हैं, जो पिछले साल बढ़कर 539 अरब डॉलर हो गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि दो प्रतिस्पर्धी ब्लॉक के उदय होने के मामले में हमें शीत युद्ध से सीख लेने की जरूरत है। *भाषा*

एनएमडीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
10–3–311/ए, कैसल हिल्स, मसब टैंक, हैदराबाद–500028, CIN: L13100AP1958GO1001674
टेलीफोनः 0091–40–23538710, 23538713 से 23538721 एक्स. 229 फैक्सः 23538781
ईमेलः jmsrao@nmdc.co.in; ksnrao@nmdc.co.in; sansari@nmdc.co.in,

निविदा आमंत्रण सूचना (जीटीई)
(ई–प्रोक्योरमेंट द्वारा केवल)

निम्नलिखित मद के लिए एमएसटीसी पोर्टल वेबसाइट **https://www.mstcecommerce.com/eprochome/nmdcbuyer_login.jsp** द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिष्ठित निर्माताओं या डीलर्स/उनके प्रमाणित एजेंटों से ई–निविदाएं आमंत्रित हैं :

निविदा सं व विवरण	बोली पूर्व बैठक	निविदा दस्तावेज प्रदर्शन व बिक्री	निविदा शुल्क व ईएमडी
HQMM/2022-18/02Z013/338 Dtd. 02/08/2019 10'' सिंगल पास बलास्ट होल ड्रिल आंतरिक स्पेयर्स के साथ 2 साल के लिए/4000 घंटे	09.08.2019 को सुबह 11.00 एनएमडीसी लिमिटेड दूसरी मंजिल, एमएम विभाग, मसब ,टैंक, हैदराबाद	ड्राफ्ट 02.08.2019 को शाम 6 से 09.08.2019 तक अंतिम 29.08.2019 से 19.09.2019	Rs.5900/- or US$ 100 and Rs. 5,00,000/- or US$ 8500

संभावित बोलीदाता हमारी वेबसाइट **www.nmdc.co.in**, सीपीपी पोर्टल **http://eprocure.gov.in, https://mstcecommerce.com** देख सकते हैं और निविदा दस्तावेज व शुद्धिपत्र, यदि कोई है, डाउनलोड कर सकते हैं। **उक्त निविदा के लिए कोई भी शुद्धिपत्र केवल हमारी वेबसाइट www.nmdc.co.in, पर ही अपलोड किए जाएंगे।**

संयुक्त उप प्रबंधक (सामग्री)

फॉर्म–जी
अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
[दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]

संबंधित विवरण	
1. कॉरपोरेट देनदार का नाम	**डिग्निटी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड**
2. कॉरपोरेट देनदार के निगमन की तिथि	02/03/2006
3. उस ऑथेरिटी का नाम, जिसके अधीन कॉरपोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, नई दिल्ली
4. कॉरपोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या	U45201DL2006PTC147034
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** डी–3, जिला केंद्र साकेत, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली –110017, भारत **कॉर्पोरेट कार्यालयः** विज़न टावर्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सैक्टर–62, गुड़गांव, हरियाणा 122102, भारत
6. कॉरपोरेट देनदार के सम्बंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	24-04-2019
7. अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण की तिथि	01-07-2019
8. कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों के लिए पात्रता निम्नलिखित पर उपलब्ध हैः	विवरण ip.dignity@in.ey.com पर ईमेल करके प्राप्त किया जा सकता है
9. धारा 29ए के अधीन लागू अयोग्यता के मानक निम्नलिखित पर उपलब्ध हैः	विवरण ip.dignity@in.ey.com पर ईमेल करके प्राप्त किया जा सकता है
10. अभिरूचि के अभिव्यक्ति के प्राप्ति की अंतिम तिथि	18-08-2019
11. संभावी समाधान आवेदकों के अनंतिम सूची निर्गमन की तिथि	23-08-2019
12. अनंतिम सूची के आपत्तियों को जमा करने की अंतिम तिथि	28-08-2019
13. संभावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची निर्गमन की तिथि	07-09-2019
14. संभावी समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स तथा समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध के निर्गमन की तिथि	28-08-2019
15. समाधान योजना के लिए अनुरोध, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	वर्चुअल डेटा रूम (वीडीआर) और इलेक्ट्रॉनिक मेल
16. समाधान योजना को जमा करने की अंतिम तिथि	27-09-2019
17. समाधान प्रोफेशनल के पास समाधान योजनाओं को जमा करने का तरीका	इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रूप से रिज़ॉल्यूशन प्लान (RFRP) के लिए अतिरिक्त विवरण जमा किया जाना चाहिए
18. अनुमोदन के लिए न्याय निर्णयन प्राधिकारी के पास समाधान योजना को जमा करने की अनुमानित तिथि	18-10-2019
19. समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	चंदर प्रकाश (IBBI/IPA-002/IP-N00660/2018-2019/12023
20. समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई–मेल, जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	नाम : चंदर प्रकाश पताः 58बी पॉकेट 4, मयूर विहार फेज – 1, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली –110091 ईमेलः cppumba2409@gmail.com
21. समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई–मेल	पताः तृतीय तल, टॉवर बी, वर्ल्डमार्क–1, ऐरोसिटी–110037 ईमेलः ip.dignity@in.ey.com cppumba2409@gmail.com
22. अधिक विवरण निम्नलिखित पर या के पास उपलब्ध है	विवरण ip.dignity@in.ey.com पर ईमेल करके प्राप्त किया जा सकता है
23. फॉर्म–जी के प्रकाशन की तिथि	03-08-2019

चंद्र प्रकाश
IBBI/IPA-002/IP-N00660/2018-2019/12023
58 बी पॉकेट 4, मयूर विहार फेज 1, नई दिल्ली,
कृते डिग्निटी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड

तिथिः 03.08.2019
स्थानः नई दिल्ली

तारा चंद लॉजिस्टिक सलूशन्स लिमिटेड
CIN: L63090CH2012PLC033556
पंजीकृत कार्यालयः 342, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज I, चंडीगढ़-160002, भारत
दूरभाषः 0172-2650380 वेबसाइटः www.tarachanindia.in

7वीं वार्षिक साधारण बैठक ('एजीएम') की सूचना
बही बंद रहने की जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि संबंधित एजीएम के आह्वान की सूचना में उल्लिखित व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए तारा चंद लॉजिस्टिक सलूशन्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 7वीं वार्षिक साधारण बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 को सुबह 10.30 बजे दि फर्न रेसिडेंसी, 28/8, फेज II, इंडस्ट्रियल एवं बिजनेस पार्क, चंडीगढ़-160002, भारत में आयोजित होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 91 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियमन, 2015 ('सूचीकरण विनियमन') के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियमन, 2018 के अनुपालन के तहत उक्त एजीएम के लिए कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही शुक्रवार, 16 अगस्त, 2019 से शुक्रवार 23, अगस्त, 2019 (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी। कंपनी ने बुधवार, 31 जुलाई, 2019 को कंपनी के सदस्यों को एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक प्रतिवेदन, उपस्थिति पर्ची/प्रतिनिधित्व प्रपत्र भेजने का कार्य सम्पन्न कर लिया है। सदस्यगण ध्यान दें कि एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट www.tarachanindia.in पर भी उपलब्ध है।

इसके अलावा, सेबी (पूंजी निर्गमन तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2009 के अध्याय एक्सबी के अधीन कंपनी ने अपने शेयरों को सूचीबद्ध कर लिया है। चूंकि कंपनी द्वारा ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ ग्रहण नहीं किया गया है इसलिए शेयरधारकगण सिर्फ बैठक के स्थल पर वोट डाल पाएंगे।

जिस व्यक्ति का नाम अंतिम तारीख यानी शुक्रवार, 16 अगस्त, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखरखाव किए जाने वाले लाभभोगी स्वत्वाधिकारी के रजिस्टर में दर्ज है सिर्फ वे ही बैठक में वोट डाल पाएंगे/प्रतिनिधि नियुक्त कर पाएंगे। सदस्यों से एजीएम की सूचना में मुद्रित वोटिंग से संबंधित निर्देशावलियों को सावधानीपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।

एजीएम से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न/शिकायत रहने पर सदस्यगण सुश्री निशु कंसल, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी से 342, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज I, चंडीगढ़-160002, भारत से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा cs@tarachanindia.in पर ईमेल भेज सकते हैं अथवा 0172-2650380 पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो शिकायतों का निवारण करेंगी।

निदेशक मंडल की ओर से
तारा चंद लॉजिस्टिक सलूशन्स लिमिटेड
हस्ता/-
निशु कंसल
(कंपनी सचिव)

स्थान : चंडीगढ़
दिनांक : 31/07/2019

पेइचिंग में आरसीईपी की बैठक हंगामेदार रहने के आसार

शुल्क पर होगा चीन से टकराव

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 2 अगस्त

क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) को लेकर पेइचिंग में होने वाली हाल की वार्ता शुल्क कम किए जाने, सेवाओं के कारोबार और निवेश की सुविधा देने जैसे मसलों के कारण कठिन होने जा रही है। सूत्रों ने कहा कि आरसीईपी की अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण खींचतान तेज हो गई है।

शुक्रवार को शुरू होने जा रही मंत्रिस्तरीय बैठक में सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्री आम सहमति वाले मसलों पर सहमति बनाने की कवायद करेंगे। लेकिन कारोबारी वार्ताकार जमीनी स्तर पर पिछले कुछ दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'आरसीईपी में चर्चा के 25 विषयों में से 13 पर अभी बातचीत पूरी नहीं हो सकी है, जबकि तकनीकी बातचीत गुरुवार को खत्म हो गई है।'

इन मसलों में सेवाओं का अहम कारोबार, सीमा पार पेशेवरों की आवाजाही, निवेश, विवाद समाधान और उत्पत्ति संबंधी नियम शामिल हैं। परिणामस्वरूप मंत्रियों के पास आगे बढ़ने के लिए मसले बहुत कम हैं, खासकर ऐसे समय में जब तीसरा आरसीईपी सम्मेलन नवंबर की शुरुआत में होने का प्रस्ताव है।

आरसीईपी भारत का महत्त्वाकांक्षी कारोबारी समझौता है, जिस पर अभी बातचीत चल रही है। आसियान ब्लॉक के 10 देशों के साथ भारत के मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते के आधार पर आरसीईपी में वे सभी देश शामिल होंगे, जिनका आसियान के साथ कारोबारी समझौता है। इनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं।

अब तक 26 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें से 6 मंत्रिस्तरीय बैठक है। हाल की बैठक में आसियान देशों ने जल्द समझौते पर हस्ताक्षर की इच्छा जताई और इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन को शुल्क कम करने के मसले पर एकमत होने की जरूरत है। लेकिन नई दिल्ली ने साफ कर दिया कि उल्लेखनी शुल्क छूट पहले ही दी जा रही है और भविष्य की वार्ता चीन की ओर से भी बराबर जोर देने पर ही आधारित होगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। संसद का सत्र 7 अगस्त तकबढ़ाए जाने को इसकी वजह बताई गई है, लेकिन सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि यह चीन को एक संकेत हो सकता है। भारत ज्यादतर देशों की अपील का विरोध कर रहा है, जिन्होंने तर्क दिया है कि भारत को सभी वस्तुओं पर मौजूदा कर में 90 प्रतिशत कमी कर दी है। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की ओर से मांग हो रही है कि भारत कुछ खास उत्पादों जैसे डेयरी और इंजीनियरिंग सामान के लिए अपने बाजार खोले।

सरकार पर दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मौजूदा एफटीए की समीक्षा करने का भी दबाव है, जो इन देशों के साथ भारत का कारोबारी घाटा कम करने में सक्षम नहीं रहे हैं।

भारत का सेवा पर जोर

भारत सेवाओं के कारोबार के मानकों जैसे प्रशिक्षित पेशेवरों की सभी देशों में आवाजाही पर जोर दे रहा है। इससे भारत के पेशेवरों जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अध्यापकों और नर्सों को अन्य आरसीईपी देशों में बगैर द्विपक्षीय आपसी समझौतों के काम करने का मौका मिलेगा

चीन को लेकर चिंता

सभी क्षेत्रों से जुड़े घरेलू उद्योगों ने भारत को इस समझौते में शामिल होने को लेकर सावधानी बरतने को कहा है। समझौते के बाद देश में चीन का माल पट जाने को लेकर चिंता है, जबकि भारत के निर्यात के बड़े क्षेत्र वैश्विक मांग कम होने के संकट से जूझ रहे हैं। स्टील, एल्युमीनियम, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, दवा, केमिकल्स, इंजीनियरिंग के सामान व ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने वाणिज्य मंत्री से मुलाकात कर चिंता जताई है।

जीएसटी रिफंड में देरी पर देना होगा ब्याज

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 2 अगस्त

गुजरात उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर जीएसटी रिफंड का भुगतान करने में देरी होती है तो देरी के लिए ब्याज दें। प्राधिकारियों को 9 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज भुगतान करने को कहा गया है।

एक साझेदारी फर्म सराफ नेचुरल फर्म ने जीएसटी रिफंड का दावा किया था। प्राधिकारियों द्वारा जीएसटी रिफंड में उल्लेखनीय देरी की गई। उसके बाद फर्म ने उच्च न्यायालय में रिट के माध्यम से आवेदन किया और अधिकारियों से देरी के लिए ब्याज दिए जाने की मांग की। आवेदन में कहा गया था कि अधिकारियों को प्रॉविजनल फंड का 90 प्रतिशत दावे की तिथि के 7 दिन के भीतर जारी करने का प्रावधान है।

फर्म ने कहा कि अधिकारियों ने देरी की कोई वजह नहीं बताई और उन्हें देरी को लेकर कोई नोटिस नहीं मिली, जिससे इस तरह की देरी की वजह का पता चल सके।

इसमें आगे कहा गया कि देरी की वजह से फर्म की कार्यशील पूंजी पर असर पड़ा है इसलिए उन्हें देरी से भुगतान के एवज में ब्याज दिया जाना चाहिए।

बहरहाल प्राधिकारियों– राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और जीएसटी नेटवर्क ने कहा है कि फर्म को ब्याज दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए याचिका में कोई दम नहीं है।

उच्च न्यायालय ने पाया कि कानून स्थापित है, जहां ब्याज को लेकर प्रावधान किए गए हैं कि रिफंड का भुगतान लाभकारी और गैर विभेदकारी होना चाहिए। इसलिए न्यायालय ने कहा कि प्राधिकारी 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

केपीएमजी के पार्टनर हरप्रीत सिंह ने कहा, 'यह एक अहम फैसला है क्योंकि अक्सर लंबित रिफंड दावों का निर्यातकों की कार्यशील पूंजी पर खराब असर होता है।'

उन्होंने कहा कि इस फैसले ने दावेदारों के लिए राह खोल दी है और अब करदाता की चूक न होने के बावजूद बहुत ज्यादा देरी होने पर ब्याज की मांग कर सकते हैं।

स्वच्छ व सस्ते ईंधन की ओर बढ़ रहा भारत : प्रधान

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 2 अगस्त

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि तेल के दाम में उतार चढ़ाव चुनौती बन गया है और भारत स्वच्छ व सस्ते विकल्पों की ओर जाने को तैयार है। मंत्री ने कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी गति पकड़ रहा है और भारत में अगले 8 साल में गैस के बुनियादी ढांचे पर 75 अरब डॉलर के करीब निवेश होगा।

दिल्ली में ब्लूमबर्ग एनईएफ सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि भारत ईवी को बढ़ावा देगा, लेकिन यह समग्र व एकीकृत तरीके से होगा, जिसमें स्वच्छ एवं सस्ते परिवहन के सभी साधन हों, उन पर ऊर्जा नीति में विचार किया जाएगा।

शुक्रवार को ब्लूमबर्ग एनईएफ अनुमान में कहा गया है कि भारत 2040 तक चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथा सबसे बड़ा ईवी बाजार बन सकता है और तब तक बिक्री करीब 26 लाख तक पहुंच जाने की उम्मीद है। बहरहाल भारत में 2030 तक बिक्री करीब 4 लाख तक ही रहने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ प्रधान ने कहा कि देश का ऊर्जा क्षेत्र विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक है। उन्होंने कहा, 'इस क्षेत्र को पश्चिमी देशों, एशियाई देशों और पश्चिम एशियाई देशों के स्वायत्त कोषों, पेंशन कोषों तथा दीर्घकालिक रणनीति निवेशकों ने लगातार निवेश मिलता रहा है।'

यह बयान ऐसे समय में आया है जब नॉर्वे के सरकारी पेंशन कोष समेत कुछ स्वायत्त कोषों ने जीवाश्म ईंधन से संबंधित परियोजनाओं और कंपनियों में निवेश नहीं करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि तमाम कंपनियों ने सफलतापूर्वक विदेशी बॉन्ड बाजार से धन जुटाया है और आगे के समय में वित्तपोषण का यह तरीका कई गुना बढ़ेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत से ज्यादा की दर से वृद्धि का अनुमान है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 7.5 करोड़ लोगों तक पहले ही पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा, 'हमने जब 2014 में सत्ता संभाली थी, सिर्फ 20 प्रतिशत आबादी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी थी। बहरहाल 10वीं सीजीडी बोली के दौर के बाद सीजीडी नेटवर्क का विस्तार करीब 70 प्रतिशत आबादी तक हो जाएगा।'

सीजीडी 228 भौगोलिक क्षेत्रों में उपलब्ध होगी, जिसमें 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 402 जिले शामिल होंगे और इसके दायरे में देश की 53 प्रतिशत आबादी आएगी। प्रधान ने कहा कि इस कदम से सीएनजी गलियारे बनेंगे, जिनका इस्तेमाल लंबी दूरी तक गैस पहुंचाने में किया जा सकेगा। उद्योग की ओर से उपलब्ध कराए गए लक्ष्य के आधार पर और 8 साल के आखिर में 4 करोड़ परिवार पीएनजी से जुड़े होंगे, जिनकी 2014 में संख्या 25 लाख थी।

पटरी पर वंदे भारत की रफ्तार सुस्त

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 2 अगस्त

1300 करोड़ रुपये का टेंडर 37 नई वंदे भारत ट्रेन की संचालन शक्ति व्यवस्था के लिए जल्द जारी होगा | **1,000 करोड़ रु** लागत पहली वंदे भारत ट्रेन की | **नई दिल्ली से कटरा** दूसरी वंदे भारत ट्रेन के लिए संभावित मार्ग

भारतीय रेल एल्युमीनियम बॉडी वाली ट्रेन 20 परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल सकता है। इसे वंदे भारत ट्रेन या ट्रेन 18 का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। यह ऐसे समय में सामने आया है, जो ट्रेन–18 की संचालन शक्ति व्यवस्था के दो बड़े ठेके तकनीकी वजहों से रद्द कर दिए गए हैं।

37 ट्रेनों के लिए 1,300 करोड़ रुपये का तीसरा ठेका जल्द दिए जाने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि ट्रेन–20 की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई है क्योंकि एल्युमीनियम बॉडी को छोड़कर इस ट्रेन की अन्य विशेषताओं को वंदे भारत में शामिल कर लिया गया है। एल्युमीनियम बॉडी से हाईस्पीड ट्रेनों को बेहतर रफ्तार मिलती है।

पहले चरण में 43 ट्रेन–18 मंगाने के लिए बोली आमंत्रित की गई, जबकि सिर्फ 3 के ऑर्डर दिए गए, जिसमें एक स्पेनिश दिग्गज सीएएफ और मेधा ग्रुप को मिला, जिसने पहली वंदे भारत ट्रेन की आपूर्ति की। इसके बाद ट्रेन–18 का दूसरा ठेका 37 ट्रेनों के लिए दिया गया, जिसे रद्द कर दिया गया। पहले रैक पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें 35 करोड़ रुपये संचालन शक्ति व्यवस्था पर खर्च हुए।

इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'ट्रेन–20 करीब करीब ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। बहरहाल ट्रेन–18 की तीसरी बोली जल्द आमंत्रित की जा सकती है, जिससे बहुराष्ट्रीय दिग्गज इसमें हिस्सा ले सकें।' इस परियोजना से जुड़े दो अन्य अधिकारियों ने भी इस सूचना की पुष्टि की। वंदे भारत श्रृंखला की दूसरी ट्रेन जल्द ही नई दिल्ली से कटरा के बीच शुरू की जा सकती है। इसके लिए रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। बोली पटरी से उतरने के कारण आईसीएफ बोर्ड की 45 नई वंदे भारत ट्रेन 2021–22 तक लाने की योजना में देरी हो सकती है।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसके पहले कहा था कि इस तरह की 100 ट्रेन सेट लाने की योजना है। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली स्वदेशी सेमी–हाई स्पीड ट्रेनसेट वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी को शुरू की गई थी, उसके बाद गोयल ने यह बयान दिया था।

इस ट्रेन को मेक इन इंडिया की सफलता में अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके 80 प्रतिशत कल पुर्जे स्वदेशी हैं।

शुरुआती योजना के मुताबिक मार्च 2020 तक आईसीएफ ने हर दो महीने पर एक ट्रेन सेट मंगाने और अप्रैल 2020 तक हर महीने एक रैक मंगाने की योजना बनाई थी। एक और सूत्र ने कहा कि रेलवे नई वंदे भारत ट्रेन के लिए नया मार्ग चिह्नित कर रही है, जो दीर्घावधि के हिसाब से शताब्दी और राजधानी ट्रेन की जगह ले सकती है।

उद्योग के एक दिग्गज ने कहा, 'ट्रेन–18 और ट्रेन–20 में तुलना करना उचित नहीं है। ट्रेन–20 में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था है और इसकी बॉडी भी एल्युमीनियम की होगी। ट्रेन–18 के ठेके पटरी से उतरने से दीर्घावधि के हिसाब से मेक इन इंडिया की पूरी अवधारणा में संभवत: मदद नहीं मिलेगी।'

सूत्र ने यह भी कहा कि सौदे का आकार छोटा होने के कारण एक भारतीय कंपनी ने आवंटित 2 ट्रेनों का ठेका लेने से मना कर दिया है। ट्रेन–18 और ट्रेन–20 दोनों ही नाम सरकार ने क्रमशः उन्हें शुरू किए जाने के वर्ष के आधार पर रखे थे।

यूएपीए विधेयक को संसद की मंजूरी

अर्चिस मोहन
नई दिल्ली, 2 अगस्त

संसद ने आज विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक पारित किर दिया। इसके तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को आंतकवादी ठहराने और उसकी संपत्ति जब्त करने की शक्ति मिल गई है।

राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 147 मत और विपक्ष में 42 मत पड़े। सदन में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने इसका समर्थन किया। कांग्रेस ने कहा कि वह विधेयक में किए गए कुछ संशोधनों के खिलाफ थी लेकिन इसके लिए वह सर्वोच्च न्यायालय में लड़ेगी। लोकसभा में यह 24 जुलाई को पारित किया था। लोकसभा में संप्रग की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसदों सहित विपक्ष के बहुत से सांसदों ने बहिर्गमन किया था। उनकी मांग थी कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाए।

तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित कई अन्य दलों ने इसका विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस ने विधेयक को समर्थन देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने सरकार की सार्वजनिक तौर पर आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र के पीठ में छुरा घोंपा है और अल्पसंख्यकों को धोखा दिया है। माकपा के राज्यसभा सांसद एलमराम करीम ने ट्वीट किया, 'कांग्रेस ने राज्यसभा में क्रूर यूएपीए विधेयक के पक्ष में मतदान कर भारत के लोगों को धोखा दिया है।'

बीएस सूडोकू 3501

		5	3		8	1	6	
			4		1		9	
		3				2		
	6		2		3		5	1
3		1	6	9	7	4		8
7	2		5		4		3	
		2				5		
	7		9		2			
	3	9	8		5	6		

परिणाम संख्या 3500

7	9	1	8	6	2	5	4	3
2	8	4	5	1	3	6	9	7
6	3	5	7	4	9	8	1	2
5	2	7	3	9	8	4	6	1
9	1	8	4	2	6	7	3	5
4	6	3	1	7	5	2	8	9
8	5	6	2	3	1	9	7	4
1	7	2	9	8	4	3	5	6
3	4	9	6	5	7	1	2	8

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसान
★☆☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2000/2010, जौ 1850/1875, चावल मसूरी 2275/2325, चावल मोटा 2225/2250, सरसों 3850/3860, तिल सफेद 10900/11000, सोया (टीन) 1300/1375, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1375/1450,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2000/2025, गेहूं शरबती 2800/2900, चावल शरबती सेला 3600/3650, स्टीम 3950/4000, लालमती 3400/3450, चावल (सोना) 3000/3050,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1425, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1620, फ्लैक 1525, डीएमओ 938, टरपीन लैस बोल्ड 1650

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): कोल्ड चाकू 1200/1225, रसकट 1040/1050, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3420, बुढ़ाना 3260, शामली 3210,

हापुड़
गुड़-चीनीः चीनी हाजिर 3500/3550, तिलहनः सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 3925, खलः सरसों 2000/2100, बिनौला 3450/3550, चना छिलका 1900/1950,

जयपुर
अनाजः चावल डीबी 6700/6800, गेहूं (मिल) 2080/2100, मक्की 2100/2125, बाजरा 1940/1950, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 4000/4050, ज्वार कैटलफीड 2000/2100, तेल-तिलहनः सरसों(मिल पहुंच) 4110/4120,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 1980/1985, ग्वार 4025/4080, जौ 1790/1800, सरसों लूज 3650/3675

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1900, पोपकोन मक्की 4500/4600, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4300/4350, ग्वारगम 8600/8700, बाजरा (गुजरात) 1900/1950, बाजरा (जयपुर) 1850/1900, चना 4000/4100, काबली चना 5000/6000, मूंग 5800/5900,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)144, राइसब्रान (अखाद्य) 141, खल सरसों 1850, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1560, लाल 1600, कंटीन्यूअस 1630,

लुधियाना
दाल-दलहनः राजमां चित्रा 8000/8500, अरहर दाल 7800/8300, उड़द साबुत 5750/6600, उड़द धोया 7000/8000, छिलका 6500/7000, दाल मसूर 5500/6000, चनादाल 5400/5500,

अमृतसर
चावलः बासमती (1121 नं.) स्टीम 7400/7500, सेला 6700/6800, शरबती साधारण सेला 3400/3500, शरबती स्टीम 3900/4000, धानः शरबती 1650/1700, बासमती 1121 धान 3800/3900,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4500/4520, हरियाणा 4480/4580, राजस्थान 4480/4500, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 3525/3625, सरसों खल 1970/1975,

फाजिल्का
गेहूं 2030/2040, सरसों 3850/3900, रुई (प्रति मन): (जे-34) 4560/4570, कपास देशी 5200/5300, कपास नरमा (क्विं.) 6250/6350, बिनौला (टैक्सपेड): खल 3500/3600,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2040/2050, चावल परमल कच्चा 2300/2400, से ला 2250/2325, मक्की यूपी 2150/2160, बिहार 2200/2225, दाल उड़द छिलका 6200/7600, चना देशी 4800/4900, दाल चना 5150/5300, काबली चना 4700/6000, राजमां चित्रा पुणे 6700/7400,चीन 7600/7900, शर्मिली 5500/6300, किरानाः जीरा 18000/21500, धनिया 8400/11300,

करनाल
गेहूं दड़ा 2060/2080, बासमती चावल 7400/7500, धान 1121 नं. 3700/3800, पूसा 1509 धान 3400/3450, शरबती धान 1600/1650, सेला (1509 नं.) चावल 6000/6050, स्टीम 7400/7500,

हिसार
ग्वार 4000/4050, सरसों 3600/3650, गेहूं 2000/2010,

जींद
जीएसटी अतिरिक्तः गेहूं 1900/1950, आटा (प्रति 44 किलो) 980/1000, मैदा 980/1110, देशी घी (एक ली/जार) 360/440, रिफाइंड (टीन) 1300/1330, चीनी 3550/3600, बिनौला 3800/4200,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्तः सरसों 3650/3700, खल बिनौला मोटी 3400/3600, बिनौला 3800/4200, सरसों तेल 7850/7900, गेहूं 1900/1925, ग्वार 3950/4000, जौ 1725/1750, *एनएनएस*